खाद्यान्नों के मूल्य

\+

*४३. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी
श्री उमानाथ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवदी :
श्री सोनावने :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के बढ़ते मूल्यों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार भविष्य में खाद्यान्नों के भावों पर नियंत्रण के लिये कुछ निश्चित योजना भी बनाने का विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). मोटे तौर पर मई–सितम्बर, १९६२ में कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्नों के भावों में कुछ बढ़ोतरी हुई थी। तब से इन में से अधिकांश क्षेत्रों में भावों में गिरावट का रुख देखा गया है । सरकार ने सभी संगत स्थितियों को ध्यान में रखते हुए समस्याओं पर विस्तारपूर्वक विचार किया है और भावों को बढ़ने से रोकने के लिए निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :—

(१) सस्ते अनाज की दुकानों के द्वारा खाद्यान्नों के वितरण की मात्रा बढ़ा दी गयी है । राज्य सरकारों से और सस्ते अनाज की दुकानें खोलने या प्रत्येक व्यक्ति को दिये जाने वाले गेहूं की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रार्थना की गयी है;

(२) संचय-निरोधक उपाय के रूप में खाद्यान्नों के स्टाक पर दी जाने वाली बैंक पेशगियों की स्थिति का नियमन करने के लिए पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है;

(३) थोक व्यापारियों पर लाइसेंस नियन्त्रण का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और इसे अधिक प्रभावी भी बनाया जा रहा है ;

(४) खाद्यान्न व्यापारियों की एसोसियेशनों को स्वैच्छिक नियन्त्रणों द्वारा व्यापार का नियमन करने और व्यापारिक व्यवहारों को सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ; और

(५) उत्पादन बढ़ाने, थोक व्यापार के नियमन करने, नियमित बाजार स्थापित करने, खरीद बढ़ाने, आरक्षित भण्डार बढ़ाने और ज्वार-बाजरा आदि (मिलेट) से और चावल खाने वाले क्षेत्रों में उपभोग को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालीन उपाय भी ढूंढे जा रहे हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : संकट काल में भी खाद्यान्नों के मूल्य पर नियन्त्रण करने के लिए जो उपाय अब तक आप ने बर्ते हैं यही पर्याप्त होंगे अथवा उस के लिए कोई विशेष योजना आप ने तैयार की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : अभी फिलहाल कोई विशेष योजना करने का इरादा नहीं है । एक महीने बाद देखा जायगा कि उस का क्या नतीजा होता है । इमरजेंसी को शुरू हुए दो हफ्ते हो गये हैं और

अभी तक तो उसका कोई बुरा असर पड़ता मालूम नहीं हुआ है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपभोक्ताओं और उत्पादकों इन दोनों के हितों का ध्यान रखते हुए अन्नों के जो वर्तमान मूल्य चल रहे हैं उन से क्या सरकार संतुष्ट है, यदि नहीं तो क्या जिस प्रकार से वित्त मंत्री महोदय ने स्वर्ण का मूल्य घटाने के लिए कुछ विशेष उपाय किये हैं उस तरह की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री स० का० पाटिल : जैसा कि कहा गया है, अभी तो हिन्दुस्तान में पचास हजार फ़ेयर-प्राइस शाप्स हैं । वे बढ़ कर एक लाख तक हो जायेंगी । और भी ज्यादा होंगी । हमारे पास काफी अनाज पड़ा है । इस से वह चीज़ हो सकती है । फ़िगर्ज़ तो बदल जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो लेटेस्ट फिगर्ज़ हैं, वह मैं आप के पास रखना चाहता हूं । अगस्त में फ़िगर्ज़ थे ९२.६ और सितम्बर में वे ९१.२ हो गए । गए बरस में, १९६१ में ८७.४, १९६० में ९०.४ और १९४९ में ९७.६ थे । उस से यह मालूम नहीं होता है कि दाम ऊपर जा रहे हैं । वे थोड़ा कम हो रहे हैं । इस लिए इस बारे में हम देखेंगे और अगर एक महीने में स्थिति बिगड़ जाती है, तो चूंकि डिफ़ेंस आफ़ इंडिया रूल्ज के अनुसार गवर्नमेंट को काफी पावर्ज़ हासिल हैं, इस लिए चौबीस घंटे में सब काम किया जा सकता है ।

Shri S. M. Banerjee: May I know whether any assurance has been given by the association of grain dealers that they will not increase the prices and that they will help the Government try to keep the prices in check?

Shri S. K. Patil: I have got hundreds of letters and wires from these associations that during the time of emergency not only will they not increase prices but they will not make any profit at all.

Shri Uma Nath: The hon. Minister has stated that the abolition of food zones for rice was receiving attention. Has any decision been taken?

Shri S. K. Patil: I do not think that emergency is just the time to take decisions of that type.

Shrimati Savitri Nigam: In these fair price shops which are going to be opened are things like gram etc., going to be sold or only wheat will be sold?

Shri S. K. Patil: Naturally all the things that are sold by the grocery shops.

Shri P. R. Patel: In the present crisis prices may be checked. But I want to know whether Government has made any enquiries to see whether the present prices are remunerative, whether they are more and if so by what per cent whether they are less and if so by how many per cent?

Shri S. K. Patil: If the fear is that the farmer is going to suffer by the regulation of the price, it is unfounded because we shall see that the farmer will not suffer; on the contrary the farmers will get a little more than what they have been getting.

Shri Surendranath Dwivedy: May I know whether the Government has ascertained what has been the effect of the steps that have been taken and whether they have been able to stop the upward trend of prices in Orissa?

Shri S. K. Patil: Orissa is in a little unfortunate position just now because of floods, drought, etc. Special measures are being taken. The Chief Minister was here only two or three days back and we are having another meeting in three or four days. Everything is done to rush stocks to Orissa so that the prices stabilise there.

Shri Sonavane: In calculating the increase in foodgrains price, is account taken only of the wholesale price? Consumers purchase their requirements from the rtailers. Is there any proposal to calculate the prices at the retailers' end?

Shri S. K. Patil: Of course. The consumer is concerned with the retailer and not the wholesaler and therefore every retailer will have to mark the price at which things are sold; that would be made obligatory. Those prices will be fixed by the Government in consideration of all the factors involved in each case.

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सच है कि जो गेहूं हम से १४ रुपये मन बोने के वक्त ख़रीदा गया था, उसी को हम १६ रुपए मन ख़रीद कर लाए हैं और जिन व्यापारियों ने ये मूल्य बढ़ाए हैं, उन को कोई सजा नहीं दी गई ?

श्री स० का० पाटिल : वह तो पुरानी चीज़ है । जब से इमर्जेन्सी शुरू हुई है, व्यापारियों से बहुत ज्यादा को-आपरेशन मिल रहा है । जब तक स्थिति नहीं बदलेगी, तब तक उन के ख़िलाफ़ कुछ करना मुझे अच्छा नहीं लगता है ।

श्री अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जब से सोने के बांड्ज़ .नकले हैं, तब तक गल्ले की कीमत काफ़ी गिर गई है ?

श्री स० का० पाटिल : नहीं । कितनी बढ़ी है, वह तो मैं ने बता दिया है । मैं ने अभी बताया है कि सितम्बर में क्या पोज़ीशन थी । मैं नहीं मानता हूं कि कीमत इतनी बढ़ी है जितनी कि . . . (Interruptions)

कुछ माननीय सदस्य : वह कहते हैं कि गिर गई है ।

Shri Koya: Shortage of wagons is said to be one of the reasons for the rise in prices in the deficit areas. May I know what arrangements the Government have made to meet this situation?

Shri S. K. Patil: Everything is being done. So far as the war zone is concerned, you know that is made on a war footing. So far as other things are concerned, I think the foodgrains will have priority.

Shri Sham Lal Saraf: May I know whether the Government have contemplated the relaxation of controls in the food zones, especially in the rice zone?

Shri S. K. Patil: The question of relaxation will largely depend upon how the situation develops from day to day, because, we are watching it every day as to what happens. If a favourable situation arises, then surely those would be relaxed.

श्री प्रिय गुप्त : मिनिस्टर महोदय ने बताया है कि इन्क्रीज्ड रेट्स से फ़ार्मर्ज़ को नफ़ा होता है, लेकिन जहां तक हम लोगों को ख़बर है, जो बढ़ती होती है, उस से मिडलमैन, प्राफ़िटीयरिंग मैन, फ़ायदा उठाते हैं । क्या मिनिस्टर महोदय मेहरबानी कर के यह जांच करेंगे कि वे भावों को फार्मर्ज़ के लिए नहीं घटाना चाहते या प्राफ़िटीयरिंग मैन के लिए नहीं घटाना चाहते—वह किस के फ़ायदे के लिए नहीं घटाना चाहते ?

श्री स० का० पाटिल : माननीय सदस्य ने शायद सुना नहीं है । मैं ने तो ऐसा कभी नहीं कहा है । मैं ने कहा है कि हम देखेंगे कि इस में फ़ार्मर या काश्तकार का नुक्सान न हो । और भी कोशिश हो रही है कि उस को कुछ ज्यादा मिले । जहां पर फूड डेफ़िसिट है, वहां हम इन्तज़ाम कर रहे हैं कि फ़ार्मर को थोड़ा ज्यादा दिया जाये ।

Shri Malaichami: May I know the names of commodities for which regulated markets have been established?

Shri Shinde: There are different regulations in different States about the regulated commodities, but mainly, the foodgrains like rice and wheat are regulated by the markets.

श्री भानु प्रकाश सिंह : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि चीनी हमले के बाद तेजपुर के व्यापारियों ने जो भाव बढ़ाये हैं, उस के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री स० का० पाटिल: मुझे नहीं मालूम कि कहां बढ़ाए हैं । ऐसा चीन में होगा, इधर नहीं ।

श्री राघेलाल व्यास : अभी माननीय मिनिस्टर साहब ने बतलाया है कि डेफ़िसिट एरियाज़ में काश्तकारों को कुछ ज्यादा देंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि जो सरप्लस एरिया है, वहां के किसानों को और ज्यादा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस बारे में एक समान नीति नहीं रखी जायगी और उन किसानों को भी ज्यादा नहीं दिया जायगा ?

श्री स० का० पाटिल : चूंकि हम को ज्यादा दुकानें रखनी होंगी, इस लिए प्रोक्योरमेंट तो करना पड़ेगा । दुकानों को देने के लिए तो हमें चावल और गेहूं अपने पास रखने चाहिएं । इस अवस्था में जो स्टेट्स फूड के बारे में डेफ़िसिट हैं, वहां किस तरह प्रोक्योरमेंट होगा ? वहां कुछ न कुछ प्रलोभन तो देना चाहिए । एज ए वार मेज़र अब थोड़ी चीज़ दी जायगी, ताकि हमें कोई तकलीफ़ न उठानी पड़े ।

श्री विभूति मिश्र: क्या यह सही है कि खाद्यान्न की कीमत तब बढ़ती है, जब फ़िनिश्ड गुड्ज़ का दाम बढ़ता है ? क्या सरकार ऐसा सोचती है कि खाद्यान्न और फ़िनिश्ड गुड्ज़ का दाम रेसिप्रोकल हो ?

श्री स० का० पाटिल: हमारी मिनिस्ट्री में फ़िनिश्ड गुड्ज़ नहीं हैं ।

Medicines with Thalidomide

+

*44. **Shri Eswara Reddy:**
Shri P. K. Deo:
Shri Dinen Bhattacharya:
Shri Bibhuti Mishra:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Mohan Swarup:
Shri Nambiar:
Shri Daji:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Joti Saroop:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether a large number of medicines containing thalidomide in different forms are being manufactured and marketed in the country; and

(b) if so, what steps have been taken by Government to stop the manufacture and sale of this dangerous drug in any form?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D. S. Raju): (a) Investigations made by Government of India have revealed that neither thalidomide under any name nor preparations containing thalidomide are available in the country.

(b) Does not arise. However, the Drugs Standard Control Officers at the ports have been instructed to apprise the Customs authorities to be on the look out for stray import of this drug as part of personal baggage and to advise such passengers to refrain from using it.

Shri Hari Vishnu Kamath: Apart from the question of this particular drug, thalidomide, is there any organisation or machinery to have a presale check, analysis or examination, of drugs and medicines manufactured in the public and private sector industries, before their sale in the market?

Dr. D. S. Raju: Yes, Sir; we have got a very big organisation. There are drug control inspectors all over the country.

Shri Hari Vishnu Kamath: Inspectors cannot analyse and check the drugs. I want your protection, Mr. Speaker. The answer is quite wide of the mark. Have they got any machinery to analyse and check the drugs? They have no scientists to analyse them. The senior Ministry may answer, Sir.

Dr. D. S. Raju: The drug control inspectors collect samples and send them to laboratories where the drugs are checked and analysed.